दैनिक जागरण

इंसान की तकदीर का सांचा उसी के हाथ में होता है

रहस्यमय बुखार का कहर

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में रहस्यमय बुखार से करीब डेढ़ सौ बच्चों की मौत पर राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से जवाब तलब करके बिल्कुल सही किया। यह इसलिए आवश्यक था, क्योंकि मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके में गंभीर किस्म के इंसेफलाइटिस की चपेट में आकर बच्चों के मरने का सिलसिला कायम रहने के बावजूद राज्य सरकार और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से वैसे कदम नहीं उठाए गए जैसे अपेक्षित थे। यह सही है कि उन कारणों की तह तक जाने में मुश्किल हो रही है जिनसे बच्चे उस रहस्यमय बीमारी का शिकार बन रहे हैं जिसे चमकी बुखार अथवा एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के तौर पर परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन अगर इस बीमारी से निपटने की प्रबल इच्छाशक्ति दिखाते हुए हर संभव उपायों का सहारा लिया गया होता तो शायद आज हालात कुछ दूसरे होते। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक सीमित दायरे में रहकर ही इस बीमारी से निपटने के प्रयास किए गए। आखिर इस बीमारी के कहर से बचने के लिए वैसे ही कदम क्यों नहीं उठाए जा सके जैसे इबोला अथवा निपाह वायरस से बचने के लिए उठाए गए? इससे इन्कार नहीं कि अतीत में भी मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बारिश के पहले रहस्यमय बुखार ने अपना सिर उठाया और उसके चलते कई बच्चों की मौत भी हुई, लेकिन अतीत के उदाहरण देकर कामचलाऊ रवैया अपनाने का कोई मतलब नहीं था। यह सामान्य बात नहीं कि दर्जनों बच्चों की मौत के बाद भी शासन-प्रशासन के स्तर पर यही रेखांकित करने की कोशिश हुई कि यहां तो ऐसा होता ही रहता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस बार गोरखपुर और आसपास के इलाके में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम अथवा जापानी बुखार का वैसा कहर नहीं दिखा जैसा कुछ वर्षों पहले तक दिखता था। समझना कठिन है कि बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के तौर-तरीकों से कोई सीख क्यों नहीं ले सकी? सवाल यह भी है कि मुजफ्फरपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार समय रहते सक्रिय क्यों नहीं हुई? एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के लिए गंदगी और कुपोषण के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। निःसंदेह कई बार किसी बीमारी के मूल कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उससे बचाव और उपचार के बेहतर उपाय किए जा सकें तो हालात काबू करने में मदद मिलती है। बिहार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवालों का चाहे जो जवाब दें, यह एक सच्चाई है कि मुजफ्फरपुर का श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं दिखा। ऐसा तब हुआ जब यह उत्तरी बिहार का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है और पिछले कई वर्षों से एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के मरीजों का गवाह बनता रहा है। संसाधनों के अभाव का सामना कर रहा यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल देश में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की खराब स्थिति को ही बयान करता है। आवश्यक केवल यही नहीं कि बिहार में बच्चों की मौत का सिलसिला थमे, बल्कि यह भी है कि केंद्र और राज्य सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कमर कसें।

कट मनी की फांस

पिछले कुछ दिनों से बंगाल ही नहीं पूरे देश में कट मनी को लेकर विभिन्न मीडिया में चर्चा छिड़ी है। कट मनी यानी अवैध वसूली। जिसे रंगदारी वसूली भी कह सकते हैं। पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने जनप्रतिनिधियों की बैठक में स्पष्ट कहा है कि जो भी तृणमूल नेता, विधायक, वार्ड पार्षद से लेकर किसी भी स्तर के जन प्रतिनिधि हैं और उन्होंने यदि लोगों से कट मनी लिया है तो वे उन्हें वापस कर दें। फिर क्या था ममता का यह बयान मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचते ही वसूली वाले नेताओं के लिए गले की फांस बनना शुरू हो गया। लोग ऐसे अवैध वसूली (कट मनी) लेने वाले पार्षद, सांसद व विधायक से लेकर नेताओं के खिलाफ मुखर होने लगे। मालदा, हुगली समेत कुछ जिलों में तो ऐसे कट मनी लेने वाले कुछ नेताओं व जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। परंतु अब देखा जा रहा है कि लोग खुलकर अवैध वसूली करने वाले तृणमूल जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलने लगे हैं और घर का घेराव तक करने लगे हैं। इस कट मनी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। माकपा से लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता तक इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख को घेरने में जुट गए हैं। सोमवार को विधानसभा में भी वाममोर्चा व कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर वाकआउट किया। वहीं ममता लगातार इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं की बैठक में बोल रही हैं। इस मुद्दे पर घिरता देख रविवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक लिखित बयान जारी कर कहा गया कि हमारी पार्टी में 99.99 फीसद ईमानदार लोग हैं। कुछ गलत हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई जा रही है। जिले ही नहीं खास कोलकाता में एक राज्यसभा सांसद सह वार्ड पार्षद के खिलाफ एक बिल्डर ने मीडिया के सामने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में भवन निर्माण के एवज में उक्त सांसद को 40-42 लाख रुपये दे चुके हैं। इससे अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि आज हालात क्या है? ममता का यह कदम सराहनीय है, लेकिन सतत कार्रवाई की जरूरत है।

एक बुरे अध्याय के सबक

केसी त्यागी

आपातकाल का दौर तानाशाही, भ्रष्टाचार और वंशवाद के विरुद्ध संग्राम का प्रतीक भी है। इससे सबक लेकर लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को और मजबूत किया जाना चाहिए

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के एक फैसले ने देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण इंदिरा गांधी के विरुद्ध रायबरेली से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। उस चुनाव में इंदिरा गांधी पर अनियमितता के आरोप में राजनारायण द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया, बल्कि उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। उन पर चुनाव के दौरान भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाने, स्वामी अवैतानंद को 50,000 रुपये घूस देकर रायबरेली से ही उम्मीदवार बनाने, वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करने, डीएम-एसपी की अवैध मदद लेने, मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब, कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने जैसे तमाम आरोप लगे थे। फैसले वाले दिन इंदिरा गांधी के आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी थीं जो भावी राजनीतिक घटनाक्रम की दिशा स्पष्ट कर रही थीं। कांग्रेसियों के जत्थे 'जस्टिस सिन्हा-मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए अदालती फैसले को सीआइए की साजिश भी बता रहे थे। शाम तक मंत्रिमंडल ने एक स्वर से उनके इस्तीफे को नकार दिया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने 'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' का नारा देकर उस दौर में सियासी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं। चंद्रशेखर की टोली को छोड़ सभी लोकतंत्र के चीरहरण के गवाह बने हुए थे। चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी-जेपी वार्ता का एक प्रयास भी किया था। उनका मानना था कि जेपी के सवाल व्यक्ति के नहीं व्यवस्था के खिलाफ हैं, इसलिए सरकार को जेपी जैसे संत से टकराव नहीं, बल्कि उनकी मांगों पर अमल करना चाहिए। उनकी मुहिम को समर्थन प्राप्त हो रहा था। उनके आवास पर लगभग 50 सांसद भी जुट गए थे।

वर्ष 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से शुरू हुआ महंगाई, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बड़े बदलाव की शक्ल ले रहा था। सभी दल एकजुट हो गए थे जिनमें भारतीय लोकदल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। छात्र युवा आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखकर और मोरारजी देसाई के अनशन से भयभीत होकर गुजरात विधानसभा को भंग कर नए चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस की भारी पराजय हुई और गांधीवादी नेता बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में पहली जनता सरकार बनी। इसी बदलाव की चिंगारियां बिहार में भी भड़क उठीं जहां अब्दुल गफूर के नेतृत्व वाली कांग्रेस बेबस और लाचार दिख रही थी। तब 1942 की क्रांति का नायक 1975 की युवा क्रांति का जननायक बन चुका था। 12 जून के बाद समूचा विपक्ष फिर एकजुट हुआ और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। पूरा विपक्ष राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देकर अपना विरोध दर्ज करा रहा था। देश भर के शहर,

अवधेश राजपूत

जलसे, जुलूस और विरोध प्रदर्शन के गवाह बन रहे थे। 22 जून को दिल्ली में आयोजित रैली को जेपी समेत कई अन्य बड़े नेता संबोधित करने वाले थे। शासक दल इतना भयभीत था कि उसने कोलकाता-दिल्ली के बीच की वह उड़ान ही निरस्त करा दी जिससे जेपी दिल्ली आने वाले थे। उन दिनों एक या दो उड़ानों का ही संचालन हुआ करता था।

आखिरकार 25 जून का दिन विरोध सभा के लिए तय हुआ। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। 'महंगाई और भ्रष्टाचार, सत्ता सब की जिम्मेदार', 'हिंदू-मुस्लिम सिख-ईसाई, सबके घर में है महंगाई', 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है', जैसे तमाम नारों से दिल्ली का जनजीवन ठहर सा गया था। चौधरी चरण सिंह समूची विपक्षी एकता के पक्षधर थे। अन्य दल भी जेपी आंदोलन को और धार देना चाहते थे। लोकदल की ओर से मैं स्वयं और सत्यपाल मलिक मंच पर उपस्थित थे, जो इस समय जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। मदनलाल खुराना मंच का संचालन कर रहे थे। मुख्य वक्ता के तौर पर जेपी जब संबोधन के लिए आए तब काफी देर तक नारेबाजी होती रही। जेपी ने स्पष्ट शब्दों में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और जनसमर्थन के अभाव वाली सरकार के अस्तित्व को मानने से इन्कार कर दिया।

सभा के चंद घंटों बाद ही भारतीय आजादी के बाद का सबसे मनहूस क्षण आया जब गैरकानूनी तरीके से अपनी सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक मान-मर्यादाओं को कुचलते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया गया। सभी मूलभूत अधिकार समाप्त कर दिए गए। समाचार पत्रों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। विपक्षी दलों के प्रमुख नेता नजरबंद कर दिए गए। सभा, जुलूस, प्रदर्शन सभी पर रोक लगा दी गई थी। राजनीतिक बंदियों की परिवारों से मुलाकात तक पर पाबंदी लगा दी गई। अदालतें स्वयं कैद हो चुकी थीं जो जमानत लेने और देने से साफ इन्कार कर रही थीं। एक लाख से अधिक राजनेता-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के समय मानसिक-शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ीं। पुलिस हिरासत और जेलों से मौत की खबरें आ रही थीं जिन्हें समाचार पत्रों में जगह नहीं मिलती थी। यह दौर करीब ढाई साल तक चलता रहा।

यद्यपि जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद संविधान के 44वें संशोधन के तहत आपातकाल जैसी परिस्थितियों के खतरे को निरस्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार तय किया गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में जरूरी परिवर्तन हुए जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके बावजूद संविधान और लोकतंत्र समर्थकों के समक्ष अभी भी कुछ यक्ष प्रश्न विद्यमान हैं।

वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी 'गरीबी हटाओ' नारे के दम पर सत्ता में आई थीं, लेकिन निरंतर बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहीं जिससे हालात बड़े राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में सामने आने लगे। इंदिरा गांधी के निरंकुश होने का यह पहला लक्षण था। दूसरा यह कि वह स्वयं को कांग्रेस का और धीरे-धीरे देश का पर्याय मानने लगी थीं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया था। निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं का स्थान चापलूसों ने ले लिया था। परिवारवाद का भोंडा चलन भी शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में संजय गांधी सत्ता के असंवैधानिक केंद्र भी बने।

निरंकुश शासकों को स्वतंत्र प्रेस से बड़ी चुनौती मिलती है इसलिए उस पर भी कड़ा प्रहार किया गया। कुलदीप नैयर समेत कई पत्रकारों को जेल जाना पड़ा। इंदिरा गांधी के तब अलोकतांत्रिक एवं बर्बर आचरण में बहुधा हिटलर की झलक दिखी। हिटलर ने कृत्रिम राष्ट्रवाद के दम पर चुनाव जीता और तानाशाही रुख अख्तियार किया। यूरोप में आज भी हिटलर की मृत्यु और आत्मसमर्पण के दिन को लोकतंत्र के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोकतंत्र की बयार बहती रहे। 25 जून निरंकुश ताकतों के खिलाफ तानाशाही, भ्रष्टाचार, वंशवाद के विरुद्ध संग्राम का दिन है जिससे सबक लेकर लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं को हम और मजबूत कर सकें।

(आपातकाल के दौरान जेल में रहे लेखक जद-यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

सरकार नहीं समाज है संघ का आधार

मनमोहन वैद्य

संघ की रचना यह ध्यान में रखकर की गई कि भारतीय समाज की राज्य से स्वतंत्र अपनी व्यवस्थाएं रही हैं

आम चुनाव के समय आरोप-प्रत्यारोप के घमासान में विभाजनकारी राजनीति करने वालों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी अकारण-आधारहीन आरोप लगाए और इस क्रम में वीर सावरकर और संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के वक्तव्यों को बिना संदर्भ उल्लेख कर संघ का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा, परंतु किसी ने भी संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का उल्लेख तक नहीं किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि संघ का मूल तो डॉक्टर हेडगेवार से ही है। उनके व्यक्तित्व को समझे बिना संघ को समझना संभव नहीं। चुनाव बाद उनका स्मरण भ्रामक संदर्भों की धूल छांटने और सही परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर हेडगेवार श्रेष्ठ संगठक थे। भारतीय दर्शन, संस्कृति और इतिहास को गहराई से अनुभव करने के कारण उनके मन में तत्कालीन चुनौतियों, उनके समाधान की राह और भविष्य की संकल्पनाएं स्पष्ट थीं। वह एक भविष्यद्रष्टा थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उनके मन में कैसी चिढ़ थी, यह उनके बचपन के अनेक प्रसंगों से दिखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलने वाले, अहिंसक सत्याग्रह से लेकर सशस्त्र क्रांति तक सभी मार्गों में वह सतत सक्रिय रहे, परंतु इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक मानसिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांति का महत्व भी वह बखूबी जानते थे। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संपूर्ण समाज के संगठन का कार्य आरंभ किया। 'केवल जेल जाना ही देशभक्ति नहीं है, बाहर रहकर सामाजिक जागृति भी जेल जाने के समान ही देशभक्ति का कार्य है' ऐसा उन्होंने प्रथम सत्याग्रह में भाग लेते समय 1921 में कहा था। तब उनकी आयु केवल 31 वर्ष की थी। उनका मन तत्कालीन 'राष्ट्रीय मानस' के साथ एकरस था।

दो वर्ष भारत भ्रमण के बाद 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका और बाद में यूरोप गए। चार वर्ष के बाद 1897 में पश्चिमी देशों से भारत लौटने के बाद उन्होंने देशवासियों से तीन बातें कहीं। पहली-पश्चिम से हमें संगठन करना सीखना चाहिए। दूसरी- हमें मनुष्य निर्माण करने की कोई पद्धति, तंत्र विकसित करना चाहिए और तीसरी-सभी भारतवासियों को आने वाले कुछ वर्षों के लिए अपने देवी-देवताओं को एक ओर रखकर केवल एक ही देवी की आराधना करनी चाहिए, और वह है अपनी 'भारत माता।' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन तीनों बातों का ही मूर्तरूप है।

'जातिप्रथा और उसका निर्मूलन' पुस्तक में बाबा साहेब आंबेडकर ने इसे रेखांकित किया है कि 'राजकीय क्रांति हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद ही हुई है, ऐसा

इतिहास बताता है। मार्टिन लूथर किंग द्वारा शुरू हुआ सुधार आंदोलन यूरोप के लोगों के राजकीय मुक्ति की पूर्वपीठिका थी। नैतिकतावाद ने ही इंग्लैंड और अमेरिका में राजकीय स्वतंत्रता की नींव रखी। मुस्लिम साम्राज्य की भी यही कहानी है। भारतीय इतिहास भी इसी निष्कर्ष को बल देता है। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में हुई राजकीय क्रांति के पहले भगवान बुद्ध की धार्मिक-सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। महाराष्ट्र में भी संतों के द्वारा किए गए धार्मिक-सामाजिक सुधार के बाद ही शिवाजी के नेतृत्व में वहां राजकीय क्रांति संभव हुई। गुरुनानक देव के धर्म और सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों की राज्य क्रांति हुई। यह समझना आवश्यक है कि 'किसी भी राष्ट्र की राजकीय मुक्ति के लिए प्रारंभिक आवश्यकता के नाते उसका मन और आत्मा की मुक्ति आवश्यक है। यह तथ्य ध्यान रखने वाला है कि स्वतंत्रता आंदोलन को सफल और सबल बनाने के लिए ही डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र के मन और आत्मा की मुक्ति का कार्य और साथ ही समाज संगठन का कार्य प्रारंभ किया।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'स्वदेशी समाज' नामक अपनी पुस्तक में यह बात आग्रहपूर्वक कही है कि कल्याणकारी राज्य भारतीय परंपरा नहीं है। भारत में समाज के सभी आवश्यक कार्य राज्य के अधीन नहीं रहते थे। कुछ ही महत्व के विभाग राज्य के अधीन रहते हैं और अन्न, जल, स्वास्थ्य और विद्या आदि सभी विषय समाज के अधीन रहते आए हैं। यदि एक तंबू एक ही खंभे पर खड़ा हो और वह खंभा टूट जाए तो सारी व्यवस्था धराशायी हो जाती है। इसके बजाय अगर तंबू चार-पांच खंभों पर खड़ा हो और किसी एक खंभे को क्षति पहुंचे तो वह धराशायी नहीं होता। आंतरिक मरम्मत से उसे फिर खड़ा करने की गुंजाइश रहती है। इसी तरह इस्लामिक जिहाद और ईसाई क्रूसेड ऐसे राज्यों को, जहां सभी व्यवस्थाएं केवल राज्य-आधारित थीं, शासक को परास्त कर उस राज्य के सभी लोगों को इस्लाम या ईसाइयत में धर्मांतरित कर सके। भारत में 850 वर्षों तक इस्लामिक शासकों का और 150 वर्षों तक ईसाइयों का शासन रहने पर भी वे केवल 15 प्रतिशत आबादी को इस्लाम में और तीन प्रतिशत को ईसाइयत में धर्मांतरित कर सके। ऐसा केवल भारत में ही संभव हुआ। इसका कारण भारत की समाज रचना राज्य आधारित व्यवस्था के एकमात्र खंभे पर नहीं टिकी थी। समाज की राज्य से स्वतंत्र अपनी भी व्यवस्थाएं थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना भी इन्हीं तत्वों पर हुई है। संघ का कार्य संपूर्ण स्वावलंबी है। वह राज्य पर आधारित नहीं है। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संचालित एक लाख 30 हजार से अधिक सेवा कार्यों में 90 प्रतिशत सेवा कार्य सरकारी सहायता पर आश्रित नहीं हैं।

मैं जब गुजरात में प्रांत प्रचारक था तब केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भाजपा के शासनकाल में जनजातीय विकास हेतु आवंटित राशि को वनवासी कल्याण आश्रम को देने की पहल भाजपा द्वारा हुई। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जनजातीय क्षेत्र में अनेक सेवा कार्य संचालित होते हैं, परंतु कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व संघ के एक कार्यकर्ता ने मुझसे जब पूछा कि कल्याण आश्रम सरकारी सहायता क्यों नहीं लेते तो मैंने उन्हें विनोबा भावे की भाषा में जवाब दिया कि 'सरकार के पास पैसा कहां से आता है? समाज ही सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देता है। माने सरकार नौकर है और समाज मालिक है। हम नौकर से क्यों मांगें? मालिक से मांग रहे हैं और वह दे भी रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में 'राष्ट्र के नाते संगठित होने की आवश्यकता' के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने संपूर्ण समाज को राष्ट्रीय दृष्टि से जागृत एवं सक्रिय करते हुए संपूर्ण समाज को संगठित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में शुरू किया। इसके महत्व को समझना चाहिए।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मननशीलता

भौतिक शरीर धारी का नाम मनुष्य नहीं है। जो मनन पूर्वक अपने विवेक का प्रयोग करके अपने कर्मों को करता है वही वास्तविक मनुष्य है। मननशीलता मनुष्य को अनर्थों के गर्त में गिरने से बचाती है। हमारे ग्रंथों में मनुष्य को पतन की दलदल में ले जाने वाले मुख्य रूप से चार कारणों को माना गया है। प्रथम युवावस्था, दूसरा धन-संपत्ति, तीसरा प्रभुत्व और चौथा है अविवेकता। पहले तीन कारण भी स्वयं अनर्थ के कारण न होकर अविवेकता अर्थात मननशीलता की न्यूनता के द्वारा अनर्थ का कारण बनते हैं। मननपूर्वक कार्य न करना ही आपत्तियों का आधार है।

जब मनुष्य विवेकपूर्वक कर्म करता है तो उसका परिणाम शुभ होता है। इसी मननशीलता को हमारे वेदों में मनुष्य का पथ प्रदर्शक कहा गया है। मननशीलता को दिन के समान प्रकाशमय बताया गया है। इसके विपरीत अंधकार में मार्ग में व्याप्त बाधाएं एवं रुकावटें हमें दिखाई नहीं देतीं। ठीक इसी प्रकार मननशीलता की शक्ति मनुष्य को अज्ञान रूपी अंधकार में भी प्रकाशित करती रहती है। इसी शक्ति से मनुष्य अपने जीवन पथ पर निर्भीक होकर सदैव आगे बढ़ता रहता है। मननशीलता मनुष्य को सच्ची शांति प्राप्त करवाती है। मन में शांति के कारण हमारा संपूर्ण नाड़ी संस्थान भी ठीक प्रकार से कार्य करता है। मननशीलता मनुष्य के मानसिक पटल पर व्याप्त हिंसा एवं घृणा की भावना को भी दूर कर देती है। कई बार हम देखते हैं कि जो विवेकहीन मनुष्य है वह छोटे-छोटे लड़ाई झगड़ों को इतना विस्तृत बना देता है, जिससे वह क्षण भर में हिंसा करने को तैयार हो जाता है। विवेकी मनुष्य सर्वथा हिंसा से दूर रहता है। मनन पूर्वक कार्य करने की दक्षता से छोटे-छोटे विवादों को आसानी से निपटा लेता है। वह कभी भी अपनी मानसिक एकाग्रता एवं शांति को भंग नहीं होने देता। मननशील मनुष्य ही जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। केवल मनुष्य रूप में जन्म लेने से ही हम वास्तविक मनुष्य नहीं बनते। जिसमें मननशीलता, बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित नहीं होती वह मनुष्य ही नहीं है। मननशीलता की शक्ति से जो परिपूर्ण है वही वास्तविक रूप से मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। ऐसे मनस्वी पुरुष ही समाज एवं राष्ट्र को शांति एवं समृद्धि के पथ की ओर ले जाने में सहायक होते हैं।

आचार्य दीपचंद भारद्वाज

वायु प्रदूषण से घटता जीवन

नरपत दान चारण

प्रदूषण की गंभीर समस्या का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर 10वां व्यक्ति अस्थमा का शिकार है

पर्यावरणीय क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि वायु प्रदूषण भारत में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। यह वायु में घुल रहे पीएम 2.5 कण, ओजोन एवं घर के भीतर के प्रदूषण का सामूहिक प्रभाव है। इस सामूहिक प्रभाव की वजह से भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा ढाई साल कम हो गई है। वहीं वायु प्रदूषण लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए ज्यादा जोखिमभरा है। इसके कारण एक लाख बच्चियों में से 96 की पांच साल पूरे होने से पहले ही मौत हो जाती है। ये आंकड़े वायु प्रदूषण की भयावहता को दर्शाते हैं।

इस रिपोर्ट से पहले भी कई रिपोर्टों में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में होने वाली मौतों में 12.5 फीसद का कारण वायु प्रदूषण है। प्रदूषण से भारत में 20 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है, जो पूरी दुनिया में प्रदूषण से होने वाली मौतों का एक चौथाई है। वर्ष 2016 के दौरान प्रदूषित वायु के कारण देश में पांच साल तक की उम्र के एक लाख दस हजार बच्चों की मृत्यु हुई। प्रदूषण की गंभीर समस्या का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर 10वां व्यक्ति अस्थमा का शिकार है, इससे गर्भ में पल रहे भ्रूण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कैंसर के मरीजों की तादाद दिनोंदिन बढ़ रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में त्वचा, श्वांस, लीवर, हृदय, आंख, गला आदि की अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं।

आखिर इस दमघोंटू वातावरण के लिए जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं। गंभीरता से समझना होगा कि प्रदूषण एक साइलेंट किलर है। वायु में घुलते कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड आदि धीरे-धीरे मौत के गर्त में ले जा रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते व्यापक खतरे को भांपते हुए देश और समाज को अपना नजरिया हर हालत में बदलना होगा और अपनी जिम्मेदारी समझकर त्वरित कदम उठाने होंगे। विडंबना है कि विभिन्न शोध रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुकी है कि आज वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, फिर भी इसकी गंभीरता के प्रति सजगता का अभाव है। यह चिंतनीय विषय है। कितनी दुखद बात है कि हम अपने बच्चों को यानी आने वाली पीढ़ी को जहरीली सांस दे रहे हैं।

अब समय आ गया है कि सरकार को भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। लोगों को स्वस्थ जीवन देना राज्य का कर्तव्य है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा। पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर से निर्भरता कम करनी होगी। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करना होगा। बिजली चलित वाहनों की उपलब्धता हर हाल में बढ़ानी होगी। अगर अब भी नहीं चेते तो यह भविष्य के लिए बड़ा संकट पैदा करने वाला होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राष्ट्रभाव का अनादर

हृदयनारायण दीक्षित द्वारा अपने आलेख 'राष्ट्रीय प्रतीक का निरंतर निरादर' में संसद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा व्यक्त किए गए 'वंदे मातरम' के विरोध को राष्ट्रभाव का अनादर बताना पूरी तरह से सही है। राष्ट्रभाव से प्रेरित वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने वाले बर्क को शायद इस बात का आभास नहीं है कि यह भारत का राष्ट्रगीत भी है, जिसकी अवमानना करना राष्ट्र विरोध की श्रेणी में आता है। इस दृष्टि से वंदे मातरम सहित अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर व्यक्त करना हर भारतीय का मूल कर्तव्य है। इतना ही नहीं बर्क को अपने इस्लाम धर्म की भी सही जानकारी नहीं है। इस्लाम में भी जन्मदात्री माता वंदनीय मानी जाती है। इस मां का निरादर करने वाला व्यक्ति निष्कृट माना जाता है। भारतीय मनीषा में चराचर प्रकृति को धारण करने वाली पृथ्वी को माता कहा गया है। हम जिस भूमि पर पैदा हुए हैं, उस समग्र भू-खंड को अपनी जन्म-भूमि मानकर इसे माता के समान आदर देते हैं। इन्हीं अर्थों में भारतवासियों के लिए भारत-भूमि माता के समान पूज्य है। गुलामी के दौर में अपनी इसी भारत माता के लिए असफाकउल्ला खां जैसे देशभक्त वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इतने पर भी सपा सांसद बर्क की नजर में यदि वंदे मातरम कुफ्र है तो यह उनकी भारत विरोधी मानसिकता का परिचायक है, जिसे वह भरे सदन में भी व्यक्त करने से नहीं चूके। ऐसे में यदि राष्ट्रीय प्रतीकों का निरादर करना अपराध है तो इस अपराध की सजा वंदे मातरम की अवमानना करने वाले हर भारतीय को मिलनी चाहिए, फिर वह चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या सामान्य नागरिक।

pandeyvp1960@gmail.com

पानी का बढ़ता संकट

इस समय देश के कई राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक आदि भारी सूखे की चपेट हैं। यह संकट हमें बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 10 वर्षों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मनुष्यों के साथ जानवर भी अपनी जान की आहुति लगा रहे हैं, जबकि उनका दोष भी नहीं है। आज हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ते जा रहे हैं। गर्मी चरम पर है, पानी बचा नहीं, वर्षा हो नहीं रही। यह सब ढुलमुल होते पर्यावरण की वजह से हो रहा है। सरकार एक तरफ वादा कर रही है कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन यह पानी आएगा कहां से? क्योंकि जमीन का पानी खत्म होता जा रहा है। ग्लेशियर दोगुनी गति से पिघलने शुरू गए हैं। नदियां सूखती जा रही हैं। पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा। समुद्र गर्म होता जा रहा है। पहाड़ों पर प्लास्टिक का ढेर लगना शुरू हो गया है। हमें अब नींद से जागने और सरक